



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ 1938 (श10)

(सं0 पटना 551) पटना, बृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं० 2/ सी०3-3046/2005-1938-सा0प्र0  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

5 फरवरी 2015

श्री अनिल चौधरी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-695/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय सम्प्रति उप विकास आयुक्त, मोतिहारी के विरुद्ध आयुक्त के सचिव, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के पत्रांक-1711 दिनांक 30.06.2010 द्वारा प्राप्त सूर्यगढ़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड चानन एवं पिपरिया के निर्वाचकों को वैकल्पिक परिचय-पत्र निर्गत करने में घोर अनियमितता बरतने, निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित किये बिना परिचय-पत्र निर्गत करने एवं उक्त अनियमितता के कारण मतदान पुनर्निर्धारित करने से होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए जवाबदेह होने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र-‘क’ के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8168 दिनांक 17.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया है कि विधान सभा चुनाव के दौरान जिला पदाधिकारी, लखीसराय के आदेश के अनुरूप मतदाता पहचान पर्ची वितरण का कार्य निर्धारित अवधि 04-10 फरवरी, 2005 तक पंचायत सचिव/राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से उनके द्वारा कराया गया। मतदाता पहचान पर्ची के वितरण के क्रम में अथवा वितरण के उपरांत किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी या आम मतदाताओं के द्वारा कभी भी किसी समय कोई लिखित या मौखिक शिकायत जिला पदाधिकारी अथवा निर्वाची पदाधिकारियों से नहीं की गयी, जिसकी पुष्टि जिला पदाधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे गये पत्र संख्या-403/नि० दिनांक 14.02.2005 में किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष सलाहकार श्री के० जे० राव द्वारा निर्वाचन कार्यों की समीक्षा के उपरांत दिये गये आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 3585/2005 में पारित न्यायादेश के आलोक में निलंबन आदेश को निर्गत होने की तिथि से निरस्त कर दिया गया। साथ ही इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जाँच प्रतिवेदन पर आधारित आरोपों के आधार पर घटना तिथि (13.02.2005) के कुल 09 वर्ष के उपरांत विभागीय कार्यवाही के संचालन का निर्णय कालबाधित एवं Natural Justice के सिद्धांत के विरुद्ध है।

जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा श्री चौधरी के स्पष्टीकरण पर समर्पित मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि श्री के० जे० राव द्वारा जब्त की गई 38 पंजियों पर अनियमितता संबंधी कोई टिप्पणी/मंतव्य/प्रतिवेदन अंकित नहीं होने के कारण कोई विशिष्ट आरोप गठित करना संभव नहीं है। इस स्थिति में यह प्रतीत होता है कि जब्त पंजियों के

आधार पर कोई जाँच नहीं हुई थी। प्रपत्र 'क' के साथ वर्णित साक्ष्य अपर्याप्त है तथा इनके आधार पर आरोप प्रमाणित करना संभव नहीं है।

आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-3591 दिनांक 09.12.2014 द्वारा प्राप्त आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अनिल चौधरी के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, लखीसराय के मंतव्य के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप पत्र, प्राप्त स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि वैकल्पिक परिचय पत्र वितरण-सह-प्राप्ति पंजी में निर्वाचकों द्वारा अँगूठा निशान लगाये जाने के आधार पर परिचय पत्र के गलत वितरण का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। श्री के0जे0राव, तत्कालीन सलाहकार, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भी ऐसा कोई लिखित प्रतिवेदन/आदेश संलग्न नहीं है, जिससे यह स्थापित हो कि श्री चौधरी के द्वारा किसी गलत मतदाता को वैकल्पिक परिचय पत्र वितरित किये जाने का मामला स्पष्ट रूप से पाया गया हो। संचिका एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्थापित नहीं होता है कि जिला पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी अथवा किसी प्रेक्षक के द्वारा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वितरित वैकल्पिक परिचय पत्रों की स्थलीय जाँच की गयी हो एवं मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया गया हो। निर्वाची पदाधिकारी, 169-सूर्यगढ़ा को न तो किसी व्यक्ति या राजीनतिक दल से परिचय पत्र के वितरण में हुई गड़बड़ी की सूचना प्राप्त हुई थी और न ही क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कोई शिकायत किसी से प्राप्त हुई थी। श्री चौधरी के विरुद्ध विधानसभा निर्वाचन में वैकल्पिक परिचय पत्र वितरित किये जाने में अनियमितता बरतने संबंधी प्रतिवेदित आरोप साक्ष्यों, जिला पदाधिकारी के मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री अनिल चौधरी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8168 दिनांक 17.06.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिल चौधरी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-695/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय सम्प्रति उप विकास आयुक्त, मोतिहारी के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8168 दिनांक 17.06.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

**आदेश :-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अनिल कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 551-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>